

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जयश्री साहू

1961

बनाम

अप्रैल 28

राजदेवन दुबे एवं अन्य

(पी. बी. गर्जेन्द्रगडकर, के. एन. वांचू, के. सी. दास गुप्ता और टी. एल.

वैकटराम अय्यर, न्यायमूर्तिगण)

हिन्दू विधि—विधवा द्वारा बंधक—बंधक ऋण चुकाने के लिए विधवा द्वारा विक्रय—
उत्तरभोगियों पर कब बाध्यकारी।

उच्च न्यायालय—प्रथा—पीठ का निर्णय—दूसरी पीठ पर बाध्यकारी प्रकृति—बाद की
पीठ के समक्ष पीठों के परस्पर विरोधी निर्णय—अपनाई जाने वाली प्रक्रिया—पूर्ण पीठ को
संदर्भित करने की वांछनीयता।

पी. की मृत्यु 14 जुलाई, 1932 को हुई, जो अपनी विधवा, एल. को अपने वारिस के
रूप में छोड़ गए। 21 जून, 1935 को, एल. ने एक स्वीकृत बाध्यकारी उद्देश्य के लिए
उत्तरदाताओं के पक्ष में एक जरपेशगी निष्पादित की, और 17 जून, 1943 को उसने जरपेशगी
के मोचन के लिए और कुछ अन्य आवश्यक उद्देश्यों के लिए उन संपत्तियों का एक हिस्सा
अपीलकर्ता को बेच दिया जो जरपेशगी विलेख की विषय-वस्तु थीं। उत्तरदाता जो उत्तरभोगी
थे, उन्होंने विक्रय की वैधता को चुनौती देते हुए एक वाद संस्थित किया। विचारण न्यायालय
और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विक्रय एक उचित विक्रय
था जो उत्तरभोगियों पर बाध्यकारी था। द्वितीय अपील पर, पटना उच्च न्यायालय की एक
खंड पीठ (खं.पी.) ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया और अपील स्वीकार कर ली।
न्यायाधीशों में से एक ने, यद्यपि विक्रय की आवश्यकता के संबंध में नीचे के न्यायालयों के

तथ्यों के निष्कर्षों से असहमति व्यक्त नहीं की, उसी उच्च न्यायालय के एक निर्णय का अनुसरण किया कि एक विधवा भोग बंधक के अधीन संपत्तियों को बेचकर उनके मोचन के उत्तरभोगियों के अधिकार को खतरे में नहीं डाल सकती है। उस न्यायालय के बाद के एक निर्णय में विधि का एक अलग दृष्टिकोण अपनाया गया था, लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने यह देखते हुए उस निर्णय का अनुसरण करने से इनकार कर दिया कि उस न्यायालय की प्रथा या तो बाद के निर्णय की तुलना में पिछली खंड पीठ (खं.पी.) के निर्णय का अनुसरण करने की थी या स्थिति तय करने के लिए मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की थी, लेकिन वर्तमान मामले में बाद के मार्ग को अपनाना वांछनीय नहीं था। अन्य विद्वान न्यायाधीश की यह राय थी कि विक्रय विलेख आवश्यकता द्वारा समर्थित नहीं था।

अभिनिर्धारित किया गया कि, उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि पर था कि अपीलकर्ता के पक्ष में विक्रय विलेख उत्तरभोगियों पर बाध्यकारी नहीं था।

जब संपत्ति पर कोई बंधक अस्तित्व में है, तो प्रश्न कि क्या विधवा इसे चुकाने के लिए बेच सकती है, एक ऐसा प्रश्न है जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी उचित मामले में उसके द्वारा विक्रय करने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। जो निर्धारित किया जाना है वह यह है कि क्या कार्य ऐसा है जिसे एक विवेकपूर्ण स्वामी द्वारा अपनी संपत्तियों का प्रबंधन करने के रूप में न्यायोचित ठहराया जा सकता है।

हनुमान प्रसाद बनाम मुसम्मात बाबूई, (1856) 6 एम.आई.ए. 393, वाकाजी बनाम विष्णु, (1894) आई.एल.आर. 18 बॉम. 534 और वीराराजू बनाम वेंकट रत्नम, आई.एल.आर. [1939] मद्रास 226, पर भरोसा किया गया।

दशरथ सिंह बनाम दमरी सिंह, ए.आई.आर. 1927 पटना 219, को नामंजूर किया गया।

लाल राम आसरे सिंह बनाम अंबिका लाल, 1929 पटना 216, को अनुमोदित किया गया।

आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि, जब उच्च न्यायालय की कोई पीठ विधि के किसी प्रश्न पर निर्णय देती है, तो सामान्यतः अन्य पीठों द्वारा उसका अनुसरण किया जाना चाहिए जब तक कि उनके पास उससे असहमत होने के कारण न हों, जिस स्थिति में अपनाने योग्य उचित मार्ग उस प्रश्न को पूर्ण पीठ के निर्णय के लिए संदर्भित करना होगा। जहाँ बाद की पीठ के समक्ष दो परस्पर विरोधी निर्णय रखे जाते हैं, तो बाद वाली पीठ के लिए बेहतर मार्ग यह है कि वह स्वयं यह तय किए बिना कि उसे एक पीठ के निर्णय का अनुसरण करना चाहिए या दूसरे का, मामले को पूर्ण पीठ को संदर्भित कर दे।

बुद्ध सिंह बनाम लल्हू सिंह, (1915) आई.एल.आर. 37 इला. 604, शेषम्मा बनाम वेंकट नरसिम्हाराव, आई.एल.आर. [1940] मद्रास 454, बिलिमोरिया बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ए.आई.आर. 1943 नागपुर 340 और वीरैया बनाम वेंकट सुब्बैया, ए.आई.आर. 1955 आंध्र 215, पर विचार किया गया।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1957 की दीवानी अपील संख्या 645 और 646।

1948 की द्वितीय अपील संख्या 2155 और 2156 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 9 अगस्त, 1956 के निर्णय और डिक्री से अपील।

अपीलकर्ता के लिए ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री और आर. सी. प्रसाद।

उत्तरदाता संख्या 1 से 4 के लिए आर. के. गर्ग, एम. के. राममूर्ति, एस. सी. अग्रवाल और डी. पी. सिंह।

1961. अप्रैल 28. न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया।

वैकटराम अय्यर, न्यायमूर्ति- ये अपीलें संविधान के अनुच्छेद 133(1)(सी) के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों पर 1948 की द्वितीय अपील संख्या 2155 और 2156 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हैं। इस मुकदमेबाजी के तथ्य एक सीमित दायरे में हैं। एक प्रीति दुबे की मृत्यु 14 जुलाई, 1932 को हुई, जो अपनी विधवा लॉग कुअर को अपने पीछे छोड़ गए, जो उनकी संपदा के वारिस के रूप में उत्तराधिकारी बनीं। मृतक द्वारा देय ऋणों को चुकाने के उद्देश्य से लॉग कुअर ने 21 जून, 1935 को दो व्यक्तियों, राजदेवन दुबे और कैलाश दुबे, जो अगले उत्तरभोगी भी थे, के पक्ष में 1,100 रुपये की राशि के लिए एक जरपेशगी विलेख निष्पादित किया। यह विवाद में नहीं है कि यह विलेख उत्तरभोगियों पर बाध्यकारी है। 17 जून, 1943 को, लॉग कुअर ने अपीलकर्ता को उन संपत्तियों का एक हिस्सा बेचा जो 21 जून, 1935 के जरपेशगी विलेख की विषय-वस्तु थीं, जो 1,600 रुपये के प्रतिफल के लिए था। इस राशि में से, 1,100 रुपये की राशि क्रेता के पास जरपेशगी के मोचन के लिए आरक्षित रखी गई थी, और शेष 500 रुपये का नकद भुगतान किया गया था। विक्रय विलेख में यह उल्लेख किया गया है कि पारिवारिक निवास गृह की मरम्मत के लिए 100 रुपये की राशि, कृषि उद्देश्यों के लिए दो बैल खरीदने के लिए 200 रुपये की राशि और एक कुएं की मरम्मत के लिए 200 रुपये की राशि की आवश्यकता थी, जिसे मृतक द्वारा जनता के उपयोग के लिए निर्मित किया गया था और जो उस समय जर्जर स्थिति में था। इन्हीं खर्चों को पूरा करने के लिए लॉग कुअर ने 500 रुपये जुटाए थे।

विक्रय विलेख प्राप्त करने के बाद, अपीलकर्ता ने जरपेशगी के मोचन का प्रयास किया, लेकिन जरपेशगीदारों ने राशि प्राप्त करने और संपत्ति का कब्जा सौंपने से इनकार कर दिया। अपीलकर्ता ने संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत न्यायालय में बंधक राशि जमा की और फिर मोचन के लिए स्वत्व वाद संख्या 69 वर्ष 1944 संस्थित किया। इसी बीच उत्तरभोगियों, जो यहाँ उत्तरदाता हैं, ने यह घोषणा करने के लिए स्वत्व वाद संख्या 126 वर्ष 1943 दायर किया था कि अपीलकर्ता के पक्ष में किया गया विक्रय विलेख उत्तरभोगियों

पर बाध्यकारी नहीं था। और दोनों वादों का विचारण एक साथ किया गया। पक्षकार तथ्य के कई प्रश्नों पर विवाद में थे, जिनमें से इस स्तर पर केवल एक ही महत्वपूर्ण है कि क्या अपीलकर्ता के पक्ष में किया गया विक्रय आवश्यकता द्वारा समर्थित था और उत्तरभोगियों पर बाध्यकारी था। पलामू के जिला मुंसिफ, जिन्होंने वादों का विचारण किया, ने साक्ष्यों की समीक्षा पर यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिफल की सभी चारों मर्दों के संबंध में आवश्यकता स्थापित की गई थी और यह विक्रय उत्तरभोगियों पर बाध्यकारी था। उन्होंने तदनुसार उत्तरदाताओं द्वारा दायर स्वत्व वाद संख्या 126 वर्ष 1943 को खारिज कर दिया और अपीलकर्ता द्वारा दायर स्वत्व वाद संख्या 69 वर्ष 1944 में मोचन की डिक्री प्रदान की। यहाँ के उत्तरदाताओं, उत्तरभोगियों ने पलामू के जिला मुंसिफ द्वारा पारित दोनों डिक्री के विरुद्ध अपीलें कीं और उन्हें पलामू के अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा सुना गया, जिन्होंने जिला मुंसिफ द्वारा दिए गए निष्कर्षों से सहमत होते हुए डिक्री की पुष्टि की और अपीलों को खारिज कर दिया। इन डिक्री के विरुद्ध, उत्तरदाताओं ने पटना उच्च न्यायालय में 1948 की द्वितीय अपील संख्या 2155 और 2156 दायर की। जब ये अपीलें लंबित थीं, 14 मार्च, 1952 को लॉग कुअर की मृत्यु हो गई, और उत्तरदाताओं के आवेदन पर, स्वत्व वाद संख्या 126 वर्ष 1943 के वादपत्र में कब्जे और मध्यवर्ती लाभ के लिए अनुतोष जोड़कर संशोधन किया गया। इसके बाद अपीलों की सुनवाई राय और मिश्रा, न्यायमूर्तिगण की पीठ द्वारा की गई, जिन्होंने अलग-अलग लेकिन सहमत निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता के पक्ष में विक्रय विलेख उत्तरभोगियों पर बाध्यकारी नहीं था। मुख्य निर्णय देने वाले मिश्रा, न्यायमूर्ति ने नीचे के न्यायालयों के इस निष्कर्ष से असहमति व्यक्त नहीं की कि प्रतिफल की सभी चारों मर्दों आवश्यकता द्वारा समर्थित थीं। वास्तव में, तथ्य का निष्कर्ष होने के नाते, यह द्वितीय अपील में न्यायालय पर बाध्यकारी होगा। हालांकि, उन्होंने दशरथ सिंह बनाम दमरी सिंह¹ में दिए गए निर्णय का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि एक विधवा

1 8 पट. एल.टी. 314; ए.आई.आर. 1927 पटना 219।

भोग बंधक के अधीन संपत्तियों को बेचकर उत्तरभोगियों के मोचन के अधिकार को खतरे में नहीं डाल सकती है, और इसलिए, यह विक्रय उन पर बाध्यकारी नहीं होगा। लाला राम आसरे सिंह बनाम अंबिका लाल² में एक अलग दृष्टिकोण अपनाया गया था, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक विधवा को उन संपत्तियों को बेचने से नहीं रोका गया था जो बंधक के अधीन थीं, जहाँ उसके लिए आवश्यकता थी, केवल इस तथ्य के कारण कि वे भोग बंधक के अधीन थीं जिसमें भुगतान करने का कोई व्यक्तिगत वचन नहीं था। लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने इस निर्णय का अनुसरण करने से इनकार कर दिया और इसका कारण इस प्रकार बताया:

"इसलिए, कई निर्णयों में निर्धारित इस न्यायालय की स्थापित प्रथा का अनुसरण करते हुए, इन परिस्थितियों में हमारे पास एकमात्र मार्ग या तो बाद वाले के बजाय पिछली खंड पीठ (खं.पी.) के निर्णय का अनुसरण करना होगा या स्थिति तय करने के लिए मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करना होगा। मेरी राय में, हालांकि, वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जिसमें इस मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित करना वांछनीय हो। इसलिए, इस न्यायालय के दशरथ सिंह के मामले के प्राधिकार का अनुसरण करते हुए जो वर्तमान मामले को पूरी तरह से कवर करता है, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अधीनस्थ न्यायालय के लाला राम आसरे सिंह के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करने में त्रुटि पर थे।"

परिणामस्वरूप विद्वान न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि 17 जून, 1943 का अपीलकर्ता के पक्ष में किया गया विक्रय विलेख उत्तरभोगियों पर बाध्यकारी नहीं था। राय, न्यायमूर्ति ने यह विचार व्यक्त किया कि चूंकि उत्तरभोगियों द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में विक्रय की वास्तविकता पर सवाल उठाया गया था और अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा उस बिंदु

पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया था, इसलिए उस प्रश्न पर निष्कर्ष के लिए मामले को प्रतिप्रेषित करना पड़ सकता था, लेकिन चूंकि विक्रय विलेख आवश्यकता द्वारा समर्थित नहीं था, इसलिए उन्होंने मिश्रा, न्यायमूर्ति के निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की। तदनुसार द्वितीय अपील स्वीकार कर ली गई और परिणामी अनुतोष प्रदान किए गए। इसके पश्चात, अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की अनुमति के लिए अनुच्छेद 133 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में आवेदन किया, और प्रमाणपत्र प्रदान करते हुए, रामास्वामी, मुख्य न्यायाधीश और राज किशोर प्रसाद, न्यायमूर्ति ने अपने दिनांक 27 नवंबर, 1956 के आदेश में यह टिप्पणी की कि दशरथ सिंह के मामले ⁽¹⁾ और लाला राम आसरे सिंह के मामले ⁽²⁾ के निर्णयों के बीच विरोध होने के कारण, यह बिंदु इस न्यायालय में अपील की अनुमति प्रदान करने के लिए पर्याप्त महत्व का था।

उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान करने के आदेश में संदर्भित दो प्रश्नों पर विचार करने से पहले, हम उत्तरदाताओं की ओर से उठाए गए एक तर्क पर विचार करेंगे, जो यदि सुदृढ़ पाया गया तो इन अपीलों के प्रतिप्रेषण की आवश्यकता होगी। यह तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता के पक्ष में किया गया विक्रय विलेख वास्तविक नहीं था, और जिला मुंसिफ द्वारा ऐसा ही अभिनिर्धारित किया गया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायाधीश इस प्रश्न पर निष्कर्ष दर्ज करने में विफल रहे थे, और इसलिए उस बिंदु पर निर्णय के लिए प्रतिप्रेषण होना चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया है, राय, न्यायमूर्ति इस तर्क से प्रभावित प्रतीत हुए थे। लेकिन जब इस तर्क की आगे जाँच की जाती है, तो यह पूरी तरह निराधार पाया जाता है। जिला मुंसिफ ने जो कहा था वह यह था कि "प्रीति दुबे की मृत्यु के बाद लॉंग कुअर के रिश्तेदार उसकी संपत्ति पर गिद्धों की तरह टूट पड़े थे", और यह काफी संभव था "कि विचाराधीन लेनदेन भी उन्हीं के कहने पर किया गया था और उन्हें भी इससे लाभ हुआ था।"

(1) 8 पट. एल.टी. 314; ए.आई.आर. 1927 पटना 219।

(2) 11 पट. एल.टी. 6; ए.आई.आर. 1929 पटना 216।

इसका केवल यही अर्थ है कि लौंग कुअर के रिश्तेदार संपदा की लूट के दोषी थे। लेकिन इससे अपीलकर्ता के अधिकार तब तक प्रभावित नहीं होंगे जब तक कि वह इसमें शामिल न हो, जो कि वर्तमान मामला नहीं है, और जिला मुंसिफ स्वयं इस पहलू के संदर्भ में यही टिप्पणी करते हैं:

"परंतु वर्तमान वाद में मुझे जयश्री साहू के हित पर विचार करना है जिसने पहले ही नेक नीयती से मुसम्मात को 500 रुपये का भुगतान कर दिया है और जरपेशगी के मोचन के लिए शेष 1,100 रुपये न्यायालय में जमा कर दिए हैं।"

यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता ने स्वयं नेक नीयती से कार्य किया था, अपील पर अधीनस्थ न्यायाधीश के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी और तदनुसार यह बिंदु उत्तरदाताओं के लिए खुला नहीं है।

उच्च न्यायालय के दिनांक 27 नवंबर, 1956 के आदेश में उल्लिखित बिंदुओं पर आगे विचार करते हुए, निर्णय के लिए जो पहला प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या एक विधवा द्वारा उन संपत्तियों का विक्रय, जो भोग बंधक की विषय-वस्तु हैं, उसकी शक्तियों से परे है जब बंधकदार बंधक पर देय राशि की वसूली के लिए वाद दायर नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने दशरथ सिंह बनाम दमरी सिंह⁽¹⁾ में दिए गए निर्णय के आधार पर इसका उत्तर सकारात्मक रूप में दिया है। उस मामले में अंतिम पुरुष धारक, एक सीताराम सिंह ने एक भोग बंधक बनाया था, और उनकी मृत्यु के बाद विधवा ने इस ऋण और कुछ अन्य ऋणों को चुकाने के लिए तथा अपनी पुत्री और पौत्री के विवाह के खर्चों को पूरा करने के लिए संपत्ति बेच दी थी। दास और अदामी, न्यायमूर्तिगण द्वारा यह

अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रतिफल की ये सभी मर्दे आवश्यकता द्वारा समर्थित थीं, लेकिन फिर भी विक्रय उत्तरभोगियों पर बाध्यकारी नहीं था।

(1) 8 पट. एल. टी. 314; ए.आई.आर. 1927 पटना 219।

निर्णय देने वाले दास, न्यायमूर्ति ने निम्नानुसार टिप्पणी की थी:-

"यह तर्क दिया गया है कि भोग बंधक की शर्तों के तहत अब वादियों के लिए उस बंधक का मोचन करना खुला होगा और यह बताया गया है कि उनके मोचन के अधिकार को विधवा द्वारा गिरवीदार को संपत्ति के हस्तांतरण के माध्यम से खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए था। मेरी राय में यह तर्क सही है और मान्य होना चाहिए।"

यदि विद्वान न्यायाधीश का इरादा विधि के एक अटूट प्रस्ताव के रूप में यह निर्धारित करना था कि, जब भी कोई भोग बंधक होता है, विधवा संपत्ति नहीं बेच सकती है, क्योंकि इससे उत्तरभोगी उसे मोचन करने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे, तो हमें इससे असहमत होना चाहिए। इस तरह के प्रस्ताव का समर्थन केवल तभी किया जा सकता है जब विधवा एक न्यासी की स्थिति में हो, जो उत्तरभोगियों के लाभ के लिए संपदा धारण करती हो, और उस पर संपत्तियों को संरक्षित करने और उन्हें अक्षुण्ण रूप में उन्हें सौंपने का कर्तव्य हो। हालांकि, यह कानून नहीं है। जब एक विधवा अपने पति के वारिस के रूप में उत्तराधिकारी बनती है, तो संपत्तियों का स्वामित्व, कानूनी और लाभकारी दोनों, उसमें निहित होता है। वह संपदा का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है, और उसमें उत्तरभोगियों का हित केवल *उत्तराधिकार की प्रत्याशा* मात्र है। विधवा संपदा के पूर्ण लाभकारी उपभोग की हकदार है और वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। यह सत्य है कि वह संपत्तियों का अन्यसंक्रमण तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वह आवश्यकता या संपदा के लाभ के लिए न हो, परंतु उसकी शक्तियों पर यह प्रतिबंध उत्तरभोगियों के लाभ के लिए लगाया गया प्रतिबंध नहीं है, बल्कि हिन्दू

विधि के अनुसार संपदा की एक विशिष्टता है। इसी कारण से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब सरकार राजगामी द्वारा संपत्ति लेती है, तो वह इसे अंतिम पुरुष धारक की विधवा द्वारा किए गए किसी भी ऐसे अन्यसंक्रमण से मुक्त लेती है जो हिन्दू विधि के तहत मान्य नहीं है, देखिए: *क्लेक्टर ऑफ मसूलीपट्टनम बनाम कावली वेंकट*⁽¹⁾। जहाँ, हालांकि, हस्तांतरण की आवश्यकता है, वहाँ अन्यसंक्रमण की उसकी शक्ति पर हिन्दू विधि द्वारा लगाया गया प्रतिबंध समाप्त हो जाता है, और विधवा को स्वामी के रूप में यह निर्णय लेने का पूर्ण विवेक प्राप्त है कि अन्यसंक्रमण का स्वरूप क्या होना चाहिए। इस संबंध में उसकी शक्तियाँ, जैसा कि *'हनुमान प्रसाद बनाम मुसम्मात बाबूई'*⁽²⁾ से शुरू होने वाले निर्णयों की एक श्रृंखला में अभिनिर्धारित किया गया है, एक शिशु की संपदा के प्रबंधक या एक संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रबंधक के समान हैं। *'वेंकाजी बनाम विष्णु'*⁽³⁾ में यह टिप्पणी की गई थी कि—

"एक परिवार के प्रबंधक के समान एक विधवा को, अपनी शक्तियों के प्रयोग में एक उचित छूट दी जानी चाहिए, बशर्ते, 'वह अपने भावी उत्तराधिकारियों के प्रति निष्पक्ष रूप से कार्य करे'।"

और हाल ही में, इस प्रश्न पर चर्चा करते हुए, *'वीराराजू बनाम वेंकट रत्नम'*⁽⁴⁾ में यह टिप्पणी की गई थी:—

"बिल्कुल इस दायित्व को कैसे निभाया जाना है, चाहे वह बंधक द्वारा हो, विक्रय द्वारा या अन्य साधनों द्वारा, इसे सख्त नियमों या कानूनी सूत्रों द्वारा निर्धारित नहीं किया जाना है, बल्कि इसे बाध्य पक्ष के उचित विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। *दुर्भावना* या फिजूलखर्ची की अनुपस्थिति में, और जब तक कि यह न तो चरित्र में अनुचित हो और न ही विस्तार में अनुवेचित, न्यायालय अन्यसंक्रमण के तरीके या मात्रा की बहुत सूक्ष्मता से जाँच नहीं करेगा।"

(1) (1861) 8 एम.आई.ए. 529।

(2) (1856) 6 एम.आई.ए. 393।

(3) (1894) 18 बॉम. 534, 536।

(4) आई.एल.आर. [1939] मद्रास 226, 231।

इन सिद्धांतों के आधार पर आंके जाने पर, जब संपत्ति पर कोई बंधक अस्तित्व में है, तो प्रश्न कि क्या विधवा इसे चुकाने के लिए बेच सकती है, एक ऐसा प्रश्न है जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी उचित मामले में उसके द्वारा विक्रय करने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। जो निर्धारित किया जाना है वह यह है कि क्या कार्य ऐसा है जिसे एक विवेकपूर्ण स्वामी द्वारा अपनी संपत्तियों का प्रबंधन करने के रूप में न्यायोचित ठहराया जा सकता है। यदि संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय के मूल्य में वृद्धि हुई है, तो ऋण चुकाने के लिए कुछ संपत्तियों का निपटान करना और शेष का मोचन करना एक उचित कदम होगा ताकि संपदा को आय का लाभ मिल सके। इस दृष्टिकोण से, 'दशरथ सिंह' के मामले⁽¹⁾ में दिया गया निर्णय, जहाँ तक इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक विधवा द्वारा भोग बंधक के अधीन संपत्ति का विक्रय उत्तरभोगियों पर बाध्यकारी नहीं है, गलत माना जाना चाहिए।

'लाला राम आसरे सिंह' के मामले⁽²⁾ में, जो दास और फज़ल अली, न्यायमूर्तिगण का निर्णय था, तथ्य 'दशरथ सिंह' के मामले⁽¹⁾ के समान ही थे। इस तर्क पर विचार करते हुए कि उन संपत्तियों का विधवा द्वारा विक्रय, जो जरपेशगी विलेख की विषय-वस्तु थीं, उत्तरभोगियों पर बाध्यकारी नहीं था क्योंकि जरपेशगीदार संपत्तियों के कब्जे में था और वह उसके तहत देय राशि की वसूली के लिए वाद दायर नहीं कर सकता था, दास, न्यायमूर्ति ने न्यायालय का निर्णय देते हुए टिप्पणी की:—

"मेरी दृष्टि में यह एक असंभव तर्क है। ऋण वहाँ था; यह एक अस्तित्ववान ऋण था, केवल लेनदार संपदा के एक हिस्से के कब्जे में था और दीवानी न्यायालयों में वाद संस्थित करके इसे वसूल करने में असमर्थ था।

(1) 8 पट. एल. टी. 314; ए.आई.आर. 1927 पटना 219।

(2) 11 पट. एल. टी. 6; ए.आई.आर. 1929 पटना 216।

लेकिन परिणाम यह था कि आय का एक बड़ा हिस्सा बासमती कुअर से वापस ले लिया गया था, जो अपने पति की उत्तराधिकारी बनी थी। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहाँ आवश्यकता की स्थिति मौजूद है, वहाँ एक महिला वारिस अपनी मृत्यु से पहले इसे चुकाने की आशा में पैसा उधार लेने के लिए बाध्य नहीं है। न ही वह संपदा को बंधक रखने और इस तरह जीवन भर के लिए अपनी आय कम करने के लिए बाध्य है। यदि वह उचित समझे, तो वह संपदा के एक हिस्से को पूर्ण रूप से बेच देने के लिए स्वतंत्र है।"

हमारे निर्णय में, ये टिप्पणियाँ विधि की स्थिति को सही ढंग से स्पष्ट करती हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि दास, न्यायमूर्ति ने ही 'दशरथ सिंह' के मामले⁽¹⁾ और 'लाला राम आसरे सिंह' के मामले⁽²⁾ दोनों में निर्णय दिया था, और 'दशरथ सिंह' के मामले⁽¹⁾ के निर्णय का उल्लेख 'लाला राम आसरे सिंह' के मामले⁽²⁾ के निर्णय में नहीं किया गया है।

इस मामले में यह पाया गया है कि लौंग कुअर को आवश्यक उद्देश्यों के लिए 500 रुपये की राशि जुटानी थी। वह अन्य संपत्तियों को बंधक रखकर ऐसा कर सकती थी, लेकिन इससे उसके उपभोग के लिए उपलब्ध आय कम हो जाती। दूसरी ओर, 21 जून, 1935 के जरपेशगी विलेख के दायरे में आने वाली संपत्तियों के एक हिस्से के विक्रय द्वारा, वह अन्य

संपत्तियों का मोचन करने में सक्षम हुई और संपदा को उन संपत्तियों से प्राप्त आय का लाभ मिला। जिला मुंसिफ और अपील पर अधीनस्थ न्यायाधीश दोनों ने सभी तथ्यों की समीक्षा करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलकर्ता के पक्ष में किया गया विक्रय एक उचित विक्रय है जो उत्तरभोगियों पर बाध्यकारी है। हमारी राय में यह निष्कर्ष द्वितीय अपील में हमले के योग्य नहीं है।

फिर वही प्रश्न आता है कि जब एक ही उच्च न्यायालय की पीठों के निर्णयों के बीच विरोध हो, तो किस प्रथा का पालन किया जाना चाहिए। जब उच्च न्यायालय की कोई पीठ विधि के किसी प्रश्न पर निर्णय देती है, तो सामान्यतः अन्य पीठों द्वारा उसका अनुसरण किया जाना चाहिए, जब तक कि उनके पास उससे असहमत होने के कारण न हों, जिस स्थिति में अपनाने योग्य उचित मार्ग उस प्रश्न को पूर्ण पीठ के निर्णय के लिए संदर्भित करना होगा। 'बुद्ध सिंह बनाम लल्लू सिंह'⁽³⁾ में, प्रिवी काउंसिल को उस प्रक्रिया पर चर्चा करने का अवसर मिला जिसे तब अपनाया जाना चाहिए जब उच्च न्यायालय की एक पीठ पिछली पीठ द्वारा दी गई राय से भिन्न मत रखती हो। 'सुरैया भुक्ता बनाम लक्ष्मीनरसंम्मा'⁽⁴⁾ और 'चिन्नास्वामी पिल्लई बनाम कुंजू पिल्लई'⁽⁵⁾ का संदर्भ देने के बाद, जहाँ स्मृति चंद्रिका में देवानंद भट्ट द्वारा व्यक्त की गई रायों के आधार पर निर्णय दिए गए थे, प्रिवी काउंसिल ने टिप्पणी की:—

"काफी उत्सुकता की बात है कि ऊपर संदर्भित मद्रास के दोनों निर्णयों में से किसी में भी उसी न्यायालय के एक पिछले निर्णय, 'परासर भट्टर बनाम रंगराज भट्टर'⁽⁶⁾ का कोई संदर्भ नहीं है, जिसमें न्यायमूर्ति टर्नर, मुख्य न्यायाधीश भी एक पक्षकार थे। उस मामले में न तो स्मृति चंद्रिका के नियम को स्वीकार किया गया था और न ही मिताक्षरा की शाब्दिक व्याख्या का अनुसरण किया गया था।" "उसी न्यायालय में जब भी मतभेद उत्पन्न होता है, तो सामान्यतः ऐसे मामलों में उस बिंदु को पूर्ण पीठ को संदर्भित किया जाता है, और

कानून ऐसी आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान करता है। यदि उस मार्ग का अनुसरण किया गया होता, तो संभवतः उनके लॉर्डशिप के पास कम से कम एक न्यायाधीश की ओर से राय के परिवर्तन के संबंध में अधिक विस्तृत तर्क होते।" (पृष्ठ 622, 623)।

(1) 8 पट. एल.टी. 314; ए.आई.आर. 1927 पटना 219।

(2) 11 पट. एल.टी. 6; ए.आई.आर. 1929 पटना 216।

(3) (1915) आई.एल.आर. 37 इलाहाबाद 604।

(4) (1881) आई.एल.आर. मद्रास 291।

(5) (1912) आई.एल.आर. 35 मद्रास 152।

(6) (1880) आई.एल.आर. 2 मद्रास 2।

इस प्रश्न पर विचार करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने 'शेषम्मा बनाम वेंकट नरसिम्हाराव'⁽¹⁾ में टिप्पणी की:

"जब तक मामले को पूर्ण पीठ को संदर्भित नहीं किया जाता, तब तक भारतीय उच्च न्यायालय में खंडपीठ ही अपील का अंतिम न्यायालय होती है, और एक खंडपीठ को विधि के प्रश्न पर दूसरी खंडपीठ के निर्णय द्वारा स्वयं को बाध्य मानना चाहिए। इंग्लैंड में, जहाँ अपील न्यायालय है, वहाँ विभागीय न्यायालय न्यायिक शिष्टाचार के आधार पर अन्य विभागीय न्यायालयों के निर्णयों का अनुसरण करते हैं; देखिए 'द वेरा क्रूज (संख्या 2)'⁽²⁾, 'हैरिसन बनाम रिजवे'⁽³⁾, 'रत्किंस्की बनाम जैकब्स'⁽⁴⁾ और 'फिलिप्स बनाम कॉपिंग'⁽⁵⁾। यदि एक खंडपीठ विधि के किसी प्रश्न पर दूसरी खंडपीठ के निर्णय को सही स्वीकार नहीं करती है, तो अपनाने योग्य एकमात्र सही और उचित मार्ग मामले को पूर्ण पीठ को संदर्भित करना है, जिसके लिए इस न्यायालय के नियम प्रावधान करते हैं। यदि यह मार्ग नहीं अपनाया जाता है, तो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय मार्गदर्शन के बिना रह जाते हैं। एक अपीलीय पीठ द्वारा समान शक्ति वाली अपीलीय पीठ के विधि के प्रश्न पर पिछले निर्णय से खुद को बाध्य मानने से इनकार करने की अनुचितता और न्याय प्रशासन में अधीनस्थ न्यायालयों के मार्ग में आने वाली कठिनाई के

अलावा, धन की हानि और न्यायिक समय की बर्बादी के अतिरिक्त कारक भी हैं।"

(1) आई.एल.आर. [1940] मद्रास 454, 474।

(2) (1884) 9 पी.डी. 96।

(3) (1925) 133 एल.टी. 238।

(4) [1929] 1 के.बी. 24।

(5) [1935] 1 के.बी. 15।

यदि विधि विरोधाभासी निर्णयों के कारण अनिश्चितता की स्थिति में डाल दी जाती है, तो वह अपनी संपूर्ण उपयोगिता खो देगी, और इसलिए यह वांछनीय है कि मतभेद की स्थिति में प्रश्न को आधिकारिक रूप से तय किया जाना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी पीठ द्वारा दिए गए पूर्व निर्णय को उसी प्रश्न पर सुनवाई करने वाली पीठ के संज्ञान में नहीं लाया जाता है, और पूर्व निर्णय के संदर्भ के बिना एक विपरीत निर्णय दे दिया जाता है। इस पर भी चर्चा की गई है कि जब बाद की किसी पीठ के समक्ष ऐसे दो विरोधाभासी निर्णय रखे जाते हैं, तो अपनाई जाने वाली सही प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। पटना उच्च न्यायालय में ऐसी स्थितियों में यह प्रथा प्रतीत होती है कि पूर्व निर्णय का अनुसरण किया जाता है, बाद वाले का नहीं। जैसा कि 'शेषम्मा बनाम वेंकट नरसिम्हाराव' ⁽¹⁾ के निर्णय में उल्लेख किया गया है, इंग्लैंड में यह प्रथा है कि अपील न्यायालय का निर्णय सामान्य नियम के रूप में उस पर बाध्यकारी माना जाता है। इसके अपवाद भी हैं, और उनमें से एक का उल्लेख 'हल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड', तीसरे संस्करण, खंड 22, कंडिका 1687, पृष्ठ 799, 800 में इस प्रकार किया गया है:-

"न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं है यदि वह असावधानी वश दिया गया हो। कोई निर्णय तब असावधानी वश दिया गया माना जाता है जब न्यायालय ने अपने स्वयं के या समान क्षेत्राधिकार वाले

न्यायालय के पिछले निर्णय की अज्ञानता में कार्य किया हो जो उसके समक्ष विचाराधीन मामले को कवर करता था, या जब उसने 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' के निर्णय की अज्ञानता में कार्य किया हो। पूर्व स्थिति में उसे यह तय करना होगा कि किस निर्णय का अनुसरण करना है, और बाद वाली स्थिति में वह 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' के निर्णय से बाध्य है।"

'वीरैया बनाम वेंकट सुब्बैया'⁽²⁾ में आंध्र उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पूर्वोक्त परिस्थितियों में पीठ न्याय और कानूनी सिद्धांतों के अनुसार उस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए स्वतंत्र है जो दो परस्पर विरोधी पीठों में व्यक्त विचारों पर विचार करने के बाद उचित हो, देखिए *'बिलिमोरिया बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया'*⁽³⁾ में नागपुर उच्च न्यायालय का निर्णय भी। विरोधाभासी प्राधिकारियों को देखते हुए मामले की सुनवाई कर रही पीठ के लिए बेहतर मार्ग यह होगा कि वह स्वयं यह निर्णय लेने के बजाय कि उसे एक पीठ के निर्णय का पालन करना चाहिए या दूसरी का, मामले को पूर्ण पीठ को संदर्भित कर दे। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ मामले को पूर्ण न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित करेगी। परिणामस्वरूप ये अपीलें स्वीकार की जाती हैं और पूरे मामले में खर्चों सहित डिक्री दी जाती है। सुनवाई के खर्चों का एक सेट।

अपीलें स्वीकार की गईं।

(1) आई.एल.आर. [1940] मद्रास 454, 474।

(2) ए.आई.आर. 1955 आंध्र 215, 217।

(3) ए.आई.आर. 1943 नागपुर 340।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता।

समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।